

21 वीं सदी की भारतीय शिक्षा में कौशल विकास : आवश्यकता, चुनौतियां एवं समाधान डॉ० वीणा कुमारी प्राचार्या

राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद (झारखण्ड)

सार :

21वीं सदी में भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष कौशल विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में उभरा है। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, और बदलती आर्थिक संरचनाओं ने एक ऐसी कार्यबल की मांग उत्पन्न की है जो न केवल शिक्षित हो, बल्कि व्यावसायिक और जीवन-आधारित कौशल से भी लैस हो। भारत, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है, अपनी जनसांख्यिकीय संपदा को तभी सशक्त बना सकता है जब उसकी शिक्षा प्रणाली युवाओं को रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रासंगिक कौशल प्रदान करे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो मुख्यतः सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित है, वर्तमान समय की इन मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास को शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को व्यावसायिक, तकनीकी, और उद्यमिता कौशल के साथ तैयार किया जा सके। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छात्रों के बीच अवसरों की असमानता को कम करने, उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। भारत में कौशल विकास के प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे अपर्याप्त अवसंरचना, योग्य प्रशिक्षकों की कमी, और कौशल विकास के प्रति समाज में कम जागरूकता। इस आलेख में इन चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है और ऐसे समाधान सुझाए गए हैं, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को कौशल विकास के प्रति अधिक सक्षम और प्रासंगिक बना सकते हैं। उपरोक्त संदर्भ में यह आलेख 21 वीं सदी की भारतीय शिक्षा में कौशल विकास की आवश्यकता, चुनौतियां एवं समाधान पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करती है।

कुंजी शब्द : 21वीं सदी, भारतीय शिक्षा, कौशल विकास

❖ परिचय :

21वीं सदी का भारत एक तेजी से बदलता हुआ देश है, जो तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका के लिए जाना जाता है। यह सदी डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप संस्कृति, और नवाचारों के उदय का प्रतीक है, साथ ही भारत ने चंद्रयान और गगनयान जैसे अंतरिक्ष मिशनों से अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया है (कुमार, 2005)। सामाजिक स्तर पर, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुधारों की गति तेज हुई है। हालांकि, शहरीकरण, पर्यावरणीय चुनौतियां, और बढ़ती असमानता जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। वैश्विक मंच पर भारत एक मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और युवा जनसंख्या के साथ दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है।

भारत कौशल विकास के क्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी इसे वैश्विक मानकों तक पहुंचने में लंबा समय लग सकता है। देश की युवा आबादी, जो विश्व में सबसे बड़ी है, कौशल विकास के लिए एक विशाल संभावना प्रस्तुत करती है (पटेल एवं फर्नांडीस 2024)। हालांकि, कई क्षेत्रों में कौशल की कमी के कारण यह जनसांख्यिकीय लाभ चुनौती बन सकता है। विश्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार, भारत की कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी औपचारिक प्रशिक्षण से वंचित है। "स्किल इंडिया" और "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" जैसे सरकारी प्रयासों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, योग्य प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।

शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को समग्र रूप से शामिल करना आज की प्रमुख आवश्यकता है। पारंपरिक शिक्षा, जो मुख्यतः सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है, को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। छात्रों को रोजगारोन्मुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल, डिजिटल साक्षरता, और समस्या-समाधान कौशल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को कम किया जा सकता है। शिक्षा में कौशल विकास के समावेश से न केवल भारत की कार्यबल की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि यह आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी सहायक होगा।

❖ भारतीय शिक्षा में कौशल विकास की आवश्यकता:

कौशल विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति की क्षमताओं और योग्यता को बढ़ाना ताकि वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सके। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को व्यावसायिक, तकनीकी, सामाजिक, और व्यावहारिक कौशल प्रदान करती है, जो उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में न केवल रोजगार पाने में मदद करती है, बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन भी सुनिश्चित करती है। कौशल विकास में तकनीकी कौशल (जैसे प्रोग्रामिंग, मशीन संचालन), सॉफ्ट स्किल्स (संचार, नेतृत्व, टीमवर्क), और जीवन कौशल (समस्या समाधान,

समय प्रबंधन) शामिल हैं। आधुनिक युग में, जब तकनीकी और औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, कौशल विकास समाज की प्रगति और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। यह न केवल व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा देता है। भारत जैसे युवा देश के लिए, जहां बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में हैं, कौशल विकास उन्हें रोजगार योग्य बनाने और देश की उत्पादकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शिक्षा में कौशल विकास का समावेशन का अभिप्राय है पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में ऐसे कौशलों को शामिल करना, जो छात्रों को व्यावहारिक जीवन और पेशेवर दुनिया के लिए तैयार करें। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो मुख्यतः सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है, वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाती। इसे बदलने के लिए शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक, तकनीकी, और सॉफ्ट स्किल्स को शामिल करना आवश्यक है। कौशल आधारित शिक्षा छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, आईटी कौशल, उद्यमिता, भाषा दक्षता, और प्रौद्योगिकी का ज्ञान रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक हो सकता है (बनर्जी, 2024)। इसके अलावा, समस्या समाधान, नवाचार, और टीमवर्क जैसे कौशल छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। शिक्षा में कौशल विकास का समावेशन उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करता है, जिससे शिक्षा का व्यावहारिक उपयोग बढ़ता है। यह केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में उत्पादकता, नवाचार, और समग्र विकास को बढ़ावा देता है। 21 वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा में कौशल विकास की आवश्यकता निम्न प्रमुख कारणों से है-

- **21वीं सदी के समाज के अनुरूप मानव संसाधन का निर्माण:** 21वीं सदी में तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था ने ऐसे मानव संसाधन की मांग बढ़ा दी है जो कुशल, नवाचारी, और बहु-आयामी हो। भारतीय शिक्षा में कौशल विकास छात्रों को नए युग की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करता है। पारंपरिक सैद्धांतिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक, तकनीकी, और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण मानव संसाधन को रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा में कौशल विकास समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति में योगदान देने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- **स्वरोजगार एवं रोजगारपरक शिक्षा का विकास:** स्वरोजगार और रोजगारपरक शिक्षा से छात्रों को न केवल नौकरी के लिए तैयार किया जा सकता है, बल्कि उन्हें उद्यमी बनने और रोजगार सृजन करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। कौशल विकास छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान, उद्यमिता कौशल, और उद्योगों की मांग के अनुरूप तकनीकी दक्षता प्रदान करता है। यह उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है और पारंपरिक नौकरी बाजार पर निर्भरता को कम करता है।

- **वैश्विक स्तर पर दक्षता:** वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। कौशल विकास कार्यक्रमों में बहुभाषीय शिक्षा, सांस्कृतिक जागरूकता, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार व प्रौद्योगिकी का ज्ञान शामिल किया जाना चाहिए। यह युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए तैयार करता है।
- **नवाचार को बढ़ावा:** नवाचार आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार है। शिक्षा में कौशल विकास नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान प्रदान करता है (फ्रौमिन एवं अन्य 2007)। प्रायोगिक शिक्षा, अनुसंधान, और समस्या समाधान जैसे कौशल छात्रों में रचनात्मकता और नई सोच को प्रोत्साहित करते हैं।
- **उद्यमिता को बढ़ावा:** उद्यमिता शिक्षा में कौशल विकास का एक प्रमुख घटक है, जो छात्रों को नए व्यवसाय स्थापित करने और जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **समावेशी शिक्षा:** कौशल विकास के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे समाज के सभी वर्गों—महिलाओं, वंचित समुदायों, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों—को समान अवसर मिल सके। यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक है।
- **धारणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में:** धारणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास पर्यावरणीय शिक्षा, हरित प्रौद्योगिकी, और संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह छात्रों को पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और संसाधनों के सतत उपयोग के लिए तैयार करता है।

❖ **भारतीय शिक्षा में कौशल विकास को केन्द्रित प्रमुख योजनाएं एवं नीतियाँ :**

भारत में कौशल विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि देश की युवा जनसंख्या को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षा कौशल विकास का सबसे प्रभावी साधन है (अंसारी एवं खान, 2018)। भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कई पहल की हैं। इन पहलों का उद्देश्य न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़ा करना है। कौशल विकास के लिए एक प्रभावी ढांचा और रणनीति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और अन्य कई योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारतीय युवा अपने कौशल को सुधारे और उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखें। इस प्रक्रिया में प्राथमिकता विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षुता, और उद्योग-प्रासंगिक कौशल विकास पर दी जा रही है।

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य युवा वर्ग को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके तहत युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना के अंतर्गत, उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, और प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM):** यह मिशन भारत सरकार द्वारा 2009 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्रों के सहयोग से विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कामकाजी उम्र के व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इस मिशन का लक्ष्य लाखों युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है।
- **कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill Education and Training Programs):** भारतीय शिक्षा मंत्रालय के तहत विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें छात्रों को न केवल शैक्षिक बल्कि व्यावसायिक और तकनीकी कौशल भी सिखाए जाते हैं, ताकि वे भविष्य में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हों। इन कार्यक्रमों में टेलीविजन, मोबाइल फोन मरम्मत, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर विज्ञान, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, आदि जैसे कौशल शामिल होते हैं।
- **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programs):** सरकार ने युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और मार्गदर्शन मिलता है। इसमें वित्तीय प्रबंधन, विपणन, और अन्य व्यापारिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसायों को सफलता पूर्वक चला सकें।
- **स्वयं (SWAYAM) योजना:** SWAYAM एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में गुणवत्ता की उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसमें कौशल विकास के पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं, जिससे विद्यार्थी अपनी क्षमता को विकसित कर सकें और रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकें। यह योजना छात्रों को कौशल आधारित और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय शिल्प एवं ग्रामोद्योग विकास संस्थान (NISI):** यह संस्था भारत सरकार के तहत शिल्पकारों और कारीगरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास और उत्पादन के अवसर प्रदान करना है। यह कारीगरों को उन्नत तकनीकों के माध्यम से अपने उत्पादों को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करती है।

- **कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, 2015:** इस नीति का उद्देश्य गति और मानक (गुणवत्ता) के साथ बड़े पैमाने पर कौशल विकास की चुनौती का सामना करना है। यह नीति देश में कौशल गतिविधियों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है और इन्हें सामान्य मानकों के अनुरूप बनाती है। इसके माध्यम से कौशल को मांग केन्द्रों से जोड़ा जाता है और इसे बेहतर रोजगार तथा उत्पादकता से जोड़ा जाता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास को आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण मानती है और एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है। इसके अंतर्गत स्कूलों में छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने, समर्पित संस्थानों की स्थापना, शैक्षिक संस्थानों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना आदि प्रावधान शामिल हैं, जो उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन:** यह मिशन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और इसका उद्देश्य कौशल विकास प्रयासों को समेकित करना है। इस मिशन में नीति मार्गदर्शन के लिए शासी परिषद, संचालन समिति, और कार्यकारी शाखा के रूप में मिशन निदेशालय शामिल हैं। मिशन में सात उप-मिशन भी प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे संस्थागत प्रशिक्षण, अभिसरण, प्रशिक्षक, और सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाना।
- **प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके):** यह पहल प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्रों की स्थापना के लिए है, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग-संचालित पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराया जा सके। इसका उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए स्थायी संस्थागत मॉडल बनाना है।
- **जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस):** यह संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए स्वायत्त संस्थान हैं जो गैर-नवसाक्षरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करते हैं। जेएसएस का उद्देश्य कौशल विकास क्षेत्र में कार्यरत अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस):** इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **कौशल ऋण योजना:** यह योजना भारतीय बैंक संघ द्वारा संचालित की जाती है, जिसके तहत कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाता है।
- **दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई):** यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है।
- ❖ **भारत में कौशल आधारित शिक्षा से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियां:**

भारत में शिक्षा प्रणाली कई महत्वपूर्ण चुनौतियों और समस्याओं का सामना कर रही है, जिनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। यहां शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और दक्षता की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी ढेर सारी समस्याएं और चुनौतियां बनी हुई हैं, जो देश के युवा वर्ग के कौशल विकास और रोजगार में सक्षम बनाने में रुकावट डालती हैं। इन समस्याओं को दूर करना और चुनौतियों का सामना करना, कौशल आधारित शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन और देश की शिक्षा प्रणाली को प्रासंगिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संदर्भ में भारत में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं और उनसे उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि एक ठोस समाधान तैयार किया जा सके। वर्तमान समय में भारत में कौशल आधारित शिक्षा के समक्ष निम्न प्रमुख समस्याएं हैं -

- **अवसंरचना की कमी:** भारत में शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी सबसे बड़ी समस्या है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में विद्यालयों और कॉलेजों में उचित सुविधाओं की भारी कमी है। इनमें पर्याप्त कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी उपकरणों का अभाव है। इसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा और कौशल विकास पर पड़ता है, क्योंकि एक आदर्श शैक्षिक वातावरण छात्रों के विकास के लिए आवश्यक है।
- **शिक्षा संसाधन और शिक्षकों की कमी:** कौशल आधारित शिक्षा की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। भारत में, शिक्षकों की गुणवत्ता और संख्या में भारी कमी है, खासकर तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में। इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। शिक्षा संसाधनों की कमी भी इस समस्या को और गंभीर बनाती है, जिसके कारण शिक्षा का स्तर और प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- **शैक्षिक असमानता और शिक्षा विभाजन:** भारतीय शिक्षा प्रणाली में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भारी असमानता पाई जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता, और प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में अंतर होने के कारण छात्रों को समान अवसर नहीं मिल पाते। इसके अलावा, समाज के वंचित वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और पिछड़े वर्गों को शिक्षा तक सीमित पहुंच मिलती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती है। यह असमानता शिक्षा में समावेशन की दिशा में एक बड़ी चुनौती है।
- **महंगी शिक्षा:** आजकल शिक्षा महंगी हो गई है, खासकर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के मामले में। कई छात्र उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा का बढ़ता खर्च छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव डालता है, जिससे शिक्षा तक सभी की समान पहुंच संभव

नहीं हो पाती। इसे कम करने के लिए शिक्षा में फंडिंग को सुधारने और अधिक सुलभ करने की आवश्यकता है।

- **शिक्षा का व्यवसायीकरण और निजीकरण:** शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण के कारण आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मुश्किलें आ रही हैं। निजी शिक्षण संस्थान लाभ के उद्देश्य से संचालित होते हैं, जिसके कारण वे अक्सर शिक्षा के गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता। शिक्षा का निजीकरण न केवल अवसरों की असमानता को बढ़ाता है, बल्कि समाज में भेदभाव भी पैदा करता है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में बदलाव के साथ समुचित संसाधनों के संयोजन का अभाव:** शिक्षक प्रशिक्षण में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि वे छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। लेकिन वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सुधार और अपडेटेड संसाधनों का अभाव है। इसके कारण शिक्षकों के पास विद्यार्थियों को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करने की क्षमता नहीं होती, जिससे शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता।
- **रोजगार के सीमित अवसर:** भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी छात्रों के पास पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, देश में कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन उद्योगों में उपयुक्त कौशल वाली प्रतिभाओं की मांग अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है। यह बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाता है और कौशल आधारित शिक्षा के महत्व को कम करता है। रोजगार सृजन में और वृद्धि की आवश्यकता है, ताकि प्रशिक्षित युवा अपनी शिक्षा का सही उपयोग कर सकें।

वहीं भारतीय शिक्षा में कौशल विकास के समावेशन के समक्ष निम्न चुनौतियां हैं जिसका समाधान आवश्यक है -

- **विशाल जनसंख्या के लिए गुणात्मक अवसंरचना विकास:** भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का विकास एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा संस्थानों में पर्याप्त कक्षाएं, सुविधाएं, और संसाधन उपलब्ध कराना सरकार और निजी क्षेत्र के लिए एक कठिन कार्य है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए शिक्षा में निवेश बढ़ाने और संसाधनों का समान वितरण करना जरूरी है, ताकि हर छात्र को समान अवसर मिल सके।
- **कौशल आधारित शिक्षा को समावेशी शिक्षा से जोड़ना:** कौशल आधारित शिक्षा को समावेशी शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर बढ़ाने होंगे और उन्हें कौशल विकास के कार्यक्रमों से जोड़ना होगा। केवल इस तरह से ही हम शिक्षा में समानता और समावेशन ला सकते हैं।

- **रोजगार के अवसरों का सृजन करना:** भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि रोजगार योग्य कौशल भी प्रदान करना चाहिए। इसके लिए सरकार और उद्योगों को मिलकर रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने होंगे, ताकि कौशल आधारित शिक्षा के बाद छात्रों को रोजगार मिल सके। इस दिशा में मजबूत नीति और कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
- **कौशल विकास कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को जोड़ना:** कौशल विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए छात्रों को इन कार्यक्रमों से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए शिक्षा संस्थानों में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का समावेश और विद्यार्थियों को व्यावसायिक दुनिया से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ानी होगी, ताकि छात्रों को सही प्रशिक्षण मिल सके।
- **ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों को जनमानस तक ले जाना:** ग्रामीण इलाकों में कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। यहां संसाधनों की कमी, जागरूकता की कमी और शिक्षा के प्रति उत्साह का अभाव है। इसके समाधान के लिए, सरकार और गैर-सरकारी संगठन मिलकर इन क्षेत्रों में कौशल विकास के अवसर बढ़ाने और छात्रों को उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करने के प्रयासों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **पर्याप्त फंड की व्यवस्था करना:** कौशल आधारित शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। सरकार और निजी क्षेत्र को इस दिशा में निवेश बढ़ाने होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के साथ-साथ, उद्योगों और सरकारी योजनाओं को एकजुट कर फंड का सही वितरण सुनिश्चित करना होगा।
- **विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के मध्य एकीकरण लाना:** भारत में विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के बीच एकीकरण का अभाव है। इन तीनों क्षेत्रों के बीच समन्वय बढ़ाने से छात्रों को समग्र रूप से विकास के अवसर मिल सकते हैं। इसके लिए नीति निर्माता और शैक्षिक संस्थानों को मिलकर एक समग्र और समन्वित शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना होगा, जिससे सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित हो सके।

❖ **समाधान एवं इसके लिए सुझाव :**

भारत में शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगा, और इसके लिए सरकार, शिक्षा संस्थान और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले, अवसंरचना में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलकर शिक्षा संस्थानों में आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करनी चाहिए। कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और इंटरनेट सुविधाओं को बेहतर बनाना चाहिए। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा के लिए अधिक डिजिटल प्लेटफार्मों और ई-लर्निंग कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया

जाना चाहिए ताकि शिक्षा की पहुंच बढ़ाई जा सके और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

दूसरे, शिक्षा संसाधन और शिक्षकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षक केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल भी प्रदान करें। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को समय-समय पर अपडेट किया जाए ताकि वे नए कौशल और शिक्षा पद्धतियों से अवगत हो सकें। कौशल आधारित शिक्षा के लिए विशिष्ट और योग्य प्रशिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने की जरूरत है, ताकि उचित संसाधन प्रदान किए जा सकें और शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके।

तीसरे, शिक्षा में समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा में निवेश बढ़ाना और समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। साथ ही, समाज के हर वर्ग को शिक्षा में समान अवसर देना चाहिए, विशेष रूप से वंचित वर्गों को, ताकि वे भी कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। इसके लिए सरकार को अधिक समावेशी नीतियां लागू करनी चाहिए, और निजी क्षेत्र को भी इन प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। इस सन्दर्भ में निम्न प्रमुख सुझाव प्रासंगिक हैं -

1. शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन और बेहतर संसाधन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके।
2. शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए और व्यावहारिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि शिक्षक छात्रों को समुचित कौशल प्रदान कर सकें।
3. सरकारी निवेश को बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि सभी छात्रों को समान रूप से अवसर मिल सकें।
4. डिजिटल शिक्षा और ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई कम हो सके।
5. कौशल आधारित शिक्षा को प्रमुख शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि छात्रों को नौकरी के योग्य कौशल मिल सकें।
6. समाज के सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि हर छात्र को अपने विकास का पूरा अवसर मिल सके।

7. शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और छात्रों को उद्योग से जुड़ी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे वास्तविक दुनिया के लिए तैयार हो सकें।
8. रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाना चाहिए और उद्योगों से साझेदारी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।
9. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण छात्र भी समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
10. शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाने और शिक्षा के उद्देश्य को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि शिक्षा समाजिक रूप से समृद्धि का माध्यम बने।

निष्कर्ष :

21वीं सदी में भारत की शिक्षा व्यवस्था में कौशल विकास की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत विकास, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देता है। बदलते वैश्विक परिवेश में जहां तकनीकी प्रगति और नवाचार की गति तेज हो रही है, वहीं देश के युवाओं को उद्योग-आधारित, जीवन-आधारित और तकनीकी कौशल में दक्ष बनाना आवश्यक है। हालांकि, भारतीय शिक्षा में कौशल विकास को लेकर कई चुनौतियां भी हैं, जैसे अवसंरचना की कमी, शैक्षिक असमानता, महंगी शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए जरूरी है कि शिक्षा नीति में सुधार किया जाए, सही संसाधनों का आवंटन किया जाए और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाया जाए।

भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और मिशनों के तहत कौशल विकास के प्रयास किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और कौशल ऋण योजना, जो देश के युवाओं को कौशल विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यदि इन प्रयासों को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है और चुनौतियों का समाधान किया जाता है, तो भारत को 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास के मामले में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता।

संदर्भ :

1. अंसारी, टी., & खान, एम. ए. (2018). रोल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। स्किल इंडिया: ऑपच्युनिटीज एंड चैलेंजेस, 208-214।
2. कुमार, के. (2005). क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी: लेसन फ्रॉम इंडिया। इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, 40(1), 3-28।
3. पटेल, ए., & फर्नांडीस, जे. जे. (2024). द सिग्निफिकेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इन इंडिया। बोधि तरु , 8, 220-229।
4. फ्रौमिन, आई., दिवाकरन, एस., तन, एच., & सेवचेंको, वाई. (2007). स्ट्रेंथनिंग स्किल्स एंड एजुकेशन फॉर इनोवेशन। अनलीशिंग इंडिया' इनोवेशन, 129।
5. बनर्जी, आर. (2024). लर्निंग द न्यू एज स्किल्स: 21st सेंचुरी एजुकेशन। न्यू ट्रेंड्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी, 1, 305।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

- ओकाडा, ए. (2012). स्किल्स डेवलपमेंट फॉर युथ इन इंडिया: चैलेंजेज एंड ऑपच्युनिटीज। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, 15(2), 169-193।
- खद्रिया, बी. (2001). शिफ्टिंग पैराडाइम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन: द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी ट्रांजिशन टुवर्ड्स जेनरिक्स इन स्किल्ड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंटरनेशनल माइग्रेशन, 39(5), 45-71।
- जैकब्स, आर., पिचर, सी., गुप्ता, आर., & देशिष्कु, आर. (2022). मल्टी-स्किल फाउंडेशन कोर्स इन इंडिया: द हेड, हार्ट, एंड हैंड्स ऑफ 21st सेंचुरी लर्निंग। इन एजुकेशन टू बिल्ड बैक बेटर: व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम एजुकेशन रिफॉर्म फॉर अ पोस्ट-पैंडेमिक वर्ल्ड (पृ. 21-49)। चाम: स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग।
- बेहरा, बी., & गौड़, एम. (2022). स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया: ए लिटरेचर रिव्यू। जीआईएस साइंस जर्नल, 9(1), 1721-1731।
- सलुजा, ए., & कुमारी, डी. (2024). स्किल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी इंडिया: चैलेंजेज एंड ऑपच्युनिटीज। वॉल. 2, इश्यू 1, जनवरी-जून, 167-181।